

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2019 (रि.वि.)

पंजीयन दिनांक 25.01.2019

G.C.M.S. NO. :-2020/00038

मै. आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय लैण्डमार्क रेस कोर्स सर्किल, वडोदरा, कॉर्पोरेट ऑफिस आई. सी. आई. सी. आई. बैंक टावर्स, बान्द्रा कूलर्स कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई) मुम्बई एवं शाखा कार्यालय आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड, 2सी मधूबनी, मधूबन, उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री ऊंकार लाल चारण पुत्र श्री हीरालाल निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-श्रीमति मेगी बाई चारण पत्नि श्री ऊंकार लाल चारण निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

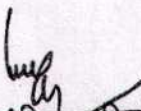
उपस्थिति : 1- श्री कैलाश चन्द्र चौखड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी



आदेश

दिनांक 19.01.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 4,90,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षीगण के सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त होने पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र उपाध्याय ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर, ऋणी/विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। दौराने बहस विपक्षी संख्या 1 तथा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

**Hypothecated Movable Secured Asset-Mahindra 475 DI, RJ-09-RB-9970, Chassis No.-RJBH06809, Engine No.-RJBH06809**

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 08.11.2017 तक कुल राशि रुपये 5,86,722/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्थोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्थोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(के. के. शर्मा)  
13/1/2021  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़